

121

संख्या-108/XXXVI(1)/2011-237 जी0/2001

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 13 जुलाई, 2011

विषय- महाधिवक्ता कार्यालय में पदों का सृजन किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 115/महा0स्था0-2008 दिनांक 11-02-07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल के लिए निम्नलिखित अस्थायी पदों को शासनादेश निर्गत होने के दिनांक अथवा भरे जाने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28-02-2012 तक के लिए बशर्ते कि इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की सं0	वेतन बैड/ग्रेड पे (रु0 में)	अभ्युक्ति
1	वरिष्ठ वाद अधीक्षक	01	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	यह पद महाधिवक्ता कार्यालय के स्थायी वाद अधीक्षको में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
2	अनुभाग अधिकारी	01	9300-34800 ग्रेड वेतन 4800	लेखा तथा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए।

2- उक्त पदों के धारको को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।

3- यदि उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तदविषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे। उक्त सृजित पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

क्रमशः.....2

4- उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आय-व्यय के अनुमान संख्या "2014 न्याय प्रशासन आयोजनेत्तर-114 विधि सलाहकार एवं परामर्शदाता (काउन्सिल) 03 महाधिवक्ता-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 338/NP/XXXVII(7)/2011 दिनांक 07 जुलाई 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०पी० गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या-108(I)/XXXVI(1)/2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. नियोजन अनुभाग/वित्त (वे०आ०-वित्त नियं०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
6. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रम सिंह खिमाल)

अपर सचिव